DIVINE
CIVIL SERVICES ACADEMY

RAS

Prelims Practice Book

राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

- टॉपिक वाइज़ अभ्यास प्रश्न
- मौलिक प्रश्नों का संकलन
- प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित

700+ अभ्यास प्रश्न
(विस्तृत व्याख्या सहित)

राजस्थान प्रैक्टिस सीरीज़ की 4 पुस्तकों की शृंखला की तीसरी कड़ी

DIVINE
CIVIL SERVICES ACADEMY

Divine Civil Services Academy के ऐप पर उपलब्ध प्रमुख कोर्सेज़

Rank Improvement Program for RAS Mains

- 500+ घंटो की कक्षाएँ
- प्रसिद्ध अध्यापकों द्वारा अध्यापन
- टॉपिक वाइज़ नोट्स
- 3 वर्ष की वैद्यता अवधि
- मेंटरशिप सपोर्ट

RAS Mains Paper 4th Target 130+ Marks

English : Prof. B. K. Rastogi

Hindi : Sh. Akhilesh Sharma

- 100+ घंटो की कक्षाएँ
- टॉपिक वाइज़ नोट्स
- 3 वर्ष की वैद्यता अवधि

RAS Prelims Test Series 2023

- Strategic Coverage of Complete Syllabus
- High Quality Questions
- Detailed Explanation Sheet for Revision

RAS Mains Test Series 2023

- Strategic Coverage of Complete Syllabus
- High Quality Questions Prepared by our Teachers
- Video Solution by our Expert Faculties
- Scientific Evaluation Methodlogy

Scan QR for our app

For more information Call:

900-900-3843

Publisher :
Divine Civil Services Academy
Main Triveni Chauraha, Gopalpura Bypass,
Jaipur-302018 • Mob.: 900-900-3843
www.divinecivilacademy.com
email: divinecivilacademy@gmail.com

© Publisher

for Trade Orders :
College Book Centre
Jaipur-4 (Raj.)
Mob.: 9001072000

RAS प्रारंभिक परीक्षा में
'राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था'
से पूछे गये प्रश्नों का ट्रेंड

विषय वस्तु	वर्ष		
	2021	2018	2016
राज्यपाल	1	1	3
मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्	1	1	–
राज्य विधानमण्डल	2	3	2
उच्च न्यायालय	1	1	–
जिला प्रशासन	1	–	1
स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्थाएँ	2	1	2
आयोग / संस्थाएँ	4	2	5
लोकनीति, विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार-पत्र	3	–	–
कुल प्रश्न	**15**	**9**	**13**

- Without the permission of the publisher, the attempt to reproduce any part of this book by any means or by any technical means (electronic, mechanical, photocopying, recording, digital, web) or the name of this book, titles, illustrations, drawings, maps, designs, cover designs, page layout, settings, literary materials, content may not be published or distributed in any language, either in whole or in part or in the form of distortions or alterations. The copyright of this book is reserved with the publisher.
- The composing work of the book has been done by the computer, in spite of taking full care by the author, proof reader, computer operator and publisher in the writing and publication work of the book, it is possible to have some incomplete or outdated information / some mistakes / shortcomings may remain. For which the printers, authors and publishers associated with the publication of the book will not be responsible. Readers' suggestions are cordially invited.
- The jurisdiction of all disputes will be Jaipur (Raj.).

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. मूल संविधान के अनुसार राज्यपाल किसी एक समय में एक ही राज्य का संवैधानिक प्रमुख हो सकता है।
2. राज्यपाल, राज्य का कार्यकारी और वास्तविक प्रमुख होता है।
3. राज्यपाल कार्यालय, इकहरी भूमिका निभाता है।

उपरोक्त में से असत्य कथन चुनिए?

(A) केवल 1 और 2 (B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3 (D) उपरोक्त सभी

उत्तर—[B]

व्याख्या— राज्यपाल का पद राज्य की शासन व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण पद है। यह राज्य विधानमण्डल का अभिन्न अंग है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है तथा केन्द्र सरकार का प्रतिनिधि भी है। इस तरह राज्यपाल एक साथ दोहरी भूमिका निभाता है।
मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसके पश्चात् संविधान के 7 वें संशोधन, 1956 के माध्यम से इसमें परंतुक जोड़कर स्पष्ट किया गया कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकेगा। संविधान के अनुच्छेद 154 और 163 दोनों प्रावधानों में दी गई व्यवस्था से यह स्पष्ट होता है कि राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख है और मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख है।

2. राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए?

1. राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 156 में किया गया है।
2. राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है।
3. राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है।

उपरोक्त में से असत्य कथन चुनिए?

(A) केवल 2 (B) केवल 3
(C) केवल 1 और 3 (D) उपरोक्त सभी

उत्तर—[D]

व्याख्या—संघात्मक देशों में राज्यपाल प्रायः जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, उदाहरण के लिए-अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इसके विपरीत कनाडा में राज्यपाल की नियुक्ति केन्द्र द्वारा की जाती है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति **कनाडा की भाँति राष्ट्रपति** द्वारा की जाती है, जो संघीय मंत्रिपरिषद् की सलाह से नियुक्ति करेंगे। यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 155 में दी गई है।

3. निम्नलिखित में से संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति हेतु कौनसी अर्हताएँ सही नहीं है?

1. वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
2. वह उस राज्य से संबंधित न हो, जहाँ उसे नियुक्त किया गया है।
3. जब राज्यपाल की नियुक्ति हो तब राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि वह राज्य के मामले में मुख्यमंत्री से परामर्श करें।

उपरोक्त में से नीचे दिए गये कूट को चुनिए

(A) 1 और 2 (B) उपरोक्त सभी
(C) 2 और 3 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर—[C]

व्याख्या—संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल के रुप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित अर्हताएँ रखनी चाहिए-

i. वह भारत का नागरिक हो।
ii. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

विगत वर्षों में इनके अतिरिक्त दो अन्य परम्पराएं भी जुड़ी है-पहला, वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए, जहाँ उसे नियुक्त किया जाना है, ताकि वो स्थानीय राजनीति से मुक्त हो। दूसरा, जब राज्यपाल की नियुक्ति हो, तब राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि वह राज्य के मामले में मुख्यमंत्री से परामर्श करें ताकि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित हो, यद्यपि दोनों परंपराओं का कुछ मामलों में उल्लंघन भी किया गया है।

4. राज्यपाल को पद से हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. राज्यपाल को उसी प्रकार पदमुक्त किया जाता है, जैसे राष्ट्रपति को।
2. राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर बना रहता है।
3. राज्यपाल, सरकार का राजनैतिक प्रमुख होता है।

उपरोक्त में से कौनसा/से कथन असत्य है?

(A) केवल 1 (B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3 (D) उपरोक्त सभी

उत्तर—[C]

व्याख्या— संविधान के अनुच्छेद-155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, लेकिन पद से हटाने के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद-156(1) में व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर बना रहेगा। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।

5. राज्यपाल की पदावधि के संबंध में संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए?

1. राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती है।
2. एक राज्यपाल 5 वर्ष के बाद भी तब तक पद पर बना रह सकता है, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण न कर लें।

उपरोक्त में से असत्य कथन चुनिए –

(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) न तो 1, ना ही 2

उत्तर—[A]

व्याख्या— अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि के संबंध में उपबंध किये गये हैं। इनमें से कुछ प्रमुख उपबंध इस प्रकार हैं-

1. राज्यपाल राष्ट्रपति के 'प्रसादपर्यंत' अपना पद धारण करेगा।
2. वह राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकेगा।
3. उपरोक्त दोनों उपबन्धों के अधीन रहते हुए 5 वर्षों की अवधि तक अपने पद पर रहेगा। साथ में यह भी प्रावधान किया गया है कि वह अपने पद की अवधि समाप्त होने पर भी पद पर बना रह सकता है, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण न कर लें।

1. 'मुख्यमंत्री की नियुक्ति' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

1. अनुच्छेद 164 (1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल की विवेकीय मनमानी है।
2. मुख्यमंत्री बनने से पहले उसे बहुमत सिद्ध करना आवश्यक है।

उपरोक्त में से असत्य कथन कौनसा है?

(A) केवल 2 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) न तो 1 और न ही 2

उत्तर—[C]

व्याख्या—भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के सदर्भ में कोई विशेष प्रक्रिया और व्यवस्था नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 164 (1) में प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जायेगी। लेकिन यह प्रावधान राज्यपाल को विवेकीय मनमानी की शक्ति प्रदान नहीं करता है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पूर्व कोई व्यक्ति बहुमत सिद्ध करें । राज्यपाल पहले उसे बतौर मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है फिर एक उचित समय के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कह सकता है। ऐसा बहुत से मामलों में हुआ है।

2. मुख्यमंत्री और मंत्रियों की योग्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. मुख्यमंत्री बनने से पहले उसे कम से कम एक बार मंत्री पद पर कार्यरत होना चाहिए।
2. किसी व्यक्ति के मंत्री बनने से पहले उसे विधानमण्डल के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए।

उपरोक्त में से असत्य कथन चुनिए –

(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) न तो 1 और न ही 2

उत्तर—[C]

व्याख्या—संविधान के भाग VI के अनुच्छेद 173 में राज्य विधानमण्डल की सदस्यता के लिए अर्हताओं को स्पष्ट किया गया है। संविधान में मुख्यमंत्री और मंत्रीगण हेतु अलग से अर्हताओं की व्यवस्था नहीं की गई है। साधारणतया विधानसभा के लिए निर्वाचित विधायक अपने में से ही मुख्यमंत्री बनाते हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए वही योग्यताएँ आवश्यक है जो एक विधायक के लिए आवश्यक होती है।

3. राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौनसा असत्य है?

(A) सबसे न्यूनतम कार्यकाल हीरालाल देवपुरा का था।
(B) भारत पाक युद्ध 1971 के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे।
(C) अनुसूचित जाति से प्रथम मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया थे।
(D) B और C दोनों

उत्तर—[B]

व्याख्या—संविधान के अनुच्छेद 164 (1) में मुख्यमंत्री के पद का प्रावधान किया गया है। राजस्थान में भारत पाक युद्ध 1971 के समय बरकतुल्ला खान मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत थे। इनका कार्यकाल 9 जुलाई 1971 से 11 अक्टुबर 1973 तक था। पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया था।

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. मुख्यमंत्री बनने के लिए दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है।
2. राजस्थान राज्य में अभी तक भैंरोंसिंह शेखावत एकमात्र मुख्यमंत्री रहे हैं, जो विधानमण्डल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे।

उपरोक्त में से कौनसा/से कथन असत्य है?

(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर—[C]

व्याख्या—संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कोई व्यक्ति दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो भी वह मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन 6 माह के भीतर उसे विधायिका से निर्वाचित हो जाना चाहिए। राजस्थान में भी भैंरोंसिंह शेखावत 1977 में जब मुख्यमंत्री बने तो विधायिका के सदस्य नहीं थे। इसके अतिरिक्त अशोक गहलोत एवं जयनारायण व्यास भी ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं, जो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते समय विधायक नहीं थे।

5. निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री लोकसभा सदस्य नहीं रहे हैं?

(A) हीरालाल शास्त्री (B) अशोक गहलोत
(C) वसुंधरा राजे (D) हरिदेव जोशी

उत्तर—[D]

व्याख्या—हरिदेव जोशी राजस्थान के तीन बार मुख्यमंत्री रहे थे। पहली बार 11 अक्टुबर 1973 से 29 अप्रैल 1977 दूसरी बार 10 मार्च 1985 से 20 जनवरी 1988, तीसरी बार 4 दिसंबर 1989 से 4 मार्च 1990 तक। उन्होंने असम, मेंघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी सेवा की थी। वह कभी भी लोकसभा सदस्य नहीं रहे थे।

6. राजस्थान में किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक उपमुख्यमंत्री रहे हैं?

(A) वसुंधरा राजे सिंधिया (B) अशोक गहलोत
(C) भैरोसिंह शेखावत (D) जयनारायण व्यास

उत्तर—[B]

व्याख्या—संविधान में उपमुख्यमंत्री पद की व्यवस्था नहीं की गई है। उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री के विवेकाधीन है। वर्तमान में सत्ता के मुख्य पदों पर आसीन होने की लालसा के कारण राजनैतिक पार्टियों ने एक रास्ता निकाला और उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति करने लगे। राजस्थान के प्रथम उपमुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। अभी तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में सर्वाधिक बार उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति की गई है, वो है 3 बार।

7. श्री अशोक गहलोत राजस्थान के पहली बार मुख्यमंत्री कब बने?

(A) 1998-2003 (B) 2004-2009
(C) 2002-2007 (D) 1993-1998

उत्तर—[A]

व्याख्या—ग्यारहवीं विधानसभा में बहुमत प्राप्त कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री अशोक गहलोत ने 1 दिसंबर 1998 को राज्य के 12 वें मुख्यमंत्री के रुप में सत्ता की बागडोर संभाली।

1. राजस्थान विधानमण्डल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. राज्य की पहली विधानसभा की पहली बैठक 29 मार्च 1952 को जयपुर के सवाई मानसिंह टाउनहॉल में संपन्न हुई थी।
2. राजस्थान की पांचवी विधानसभा के कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक बार उपचुनाव सम्पन्न हुए थे।
3. श्री हरिदेवजोशी न केवल राजस्थान अपितु भारत के एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो लगातार 10 बार विधायक रहे हैं।

उपरोक्त में कौन-सा से कथन सत्य है?

(A) केवल 1 और 2 (B) केवल 2
(C) केवल 2 और 3 (D) केवल 1 और 3

उत्तर—[B]

व्याख्या—राजस्थान में प्रथम आम चुनाव जनवरी, 1952 में सम्पन्न हुए थे। इस चुनाव में राज्य विधानसभा की पहली बैठक 29 मार्च 1952 को जयपुर के सवाईमानसिंह टाउन हॉल में सम्पन्न हुई थी। राजस्थान की प्रथम विधानसभा कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक 17 बार उपचुनाव सम्पन्न हुए। श्री हरिदेव जोशी न केवल राजस्थान अपितु भारत के एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो लगातार 10 बार विधायक रहे हैं।

2. राजस्थान विधानमण्डल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. प्रथम विधानसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल रामराज्य परिषद था।
2. 6वीं विधानसभा में पहली बार भैरोंसिंह शेखावत के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी।
3. राजस्थान में संसदीय सचिव पद की शुरुआत मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने की थी।

उपरोक्त में से कौनसा/से कथन सत्य है?

(A) केवल 1 और 2 (B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3 (D) उपरोक्त सभी।

उत्तर— [D]

व्याख्या—राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव जनवरी 1952 में सम्पन्न हुए। इस चुनाव में राज्य विधानसभा में 160 सीटें थी। जिनमें से कांग्रेस को 82 सीटें प्राप्त हुई तथा मुख्य विपक्षी दल 'रामराज्य परिषद' को 24 सीटें प्राप्त हुई। षष्ठम् विधानसभा में सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 की गई तथा पहली बार भैरोसिंह के नेतृत्व में 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार (जनता दल) बनी। राजस्थान में प्रथम बार सचिव पद की शुरुआत मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा की गई थी।

3. यदि 15 अगस्त 2023 को राजस्थान में विधानपरिषद का गठन किया जाये तो अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या क्रमश: क्या होगी?

(A) 60, 40 (B) 60, 30
(C) 66, 40 (D) 66, 30

उत्तर—[C]

व्याख्या—राज्य विधानपरिषदों के गठन की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 169 में की गई है। विधानपरिषद वाले राज्य की विधानपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी। किसी भी दशा में राज्य विधानपरिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं होगी (अनुच्छेद 171)। राजस्थान की विधानसभा सदस्य संख्या 200 है। अत:

विधानपरिषद की अधिकतम संख्या $200\frac{1}{3} = 66.61$

4. निम्नलिखित में से किन-किन राज्यों में राज्य विधान परिषद है?

1. उत्तर प्रदेश 2. कर्नाटक
3. जम्मू-कश्मीर 4. आंध्र प्रदेश
5. राजस्थान

उपरोक्त में से सत्य कथन को चुनिए -

(A) केवल 1, 2 और 4 (B) केवल 1, 2, 3 और 4
(C) केवल 1 और 4 (D) उपरोक्त सभी

उत्तर—[A]

व्याख्या—भारत में 22 राज्यों में एक सदनीय विधानमण्डल तथा 6 राज्यों में द्वि-सदनीय विधानमण्डल है और ये 6 राज्य हैं-उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद से वहां इस व्यवस्था का समापन कर दिया गया है।

5. विधानपरिषद के गठन और विघटन के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा द्वारा कुल मतों और उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से कम नहीं होना चाहिए।
2. संसद का यह अधिनियम, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन माना जायेगा।

उपरोक्त में से कौनसा/से कथन सत्य हैं?

(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) न तो 1 और न ही 2

उत्तर—[A]

व्याख्या—संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषदों के गठन एवं उत्सादन का उल्लेख किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि इस तरह का कोई विशेष प्रस्ताव राज्य विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना जरूरी है। यह बहुमत कुल मतों और उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से कम नहीं होना चाहिए। संसद का यह अधिनियम अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों हेतु संविधान का संशोधन नहीं माना जायेगा और सामान्य विधान की तरह (अर्थात् साधारण बहुमत से) पारित किया जायेगा।

6. विधानपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. राजस्थान विधानसभा में कभी भी विधानपरिषद से संबंधित प्रस्ताव पारित नहीं किया गया।
2. स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम आंध्रप्रदेश राज्य में विधानपरिषद का गठन किया गया।

उपरोक्त में से कौनसा/से कथन सत्य हैं—

(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) न तो 1, ना ही 2

उत्तर—[B]

1. भारत में सर्वप्रथम सन् 1862 में कौनसे उच्च न्यायालयों का गठन किया गया था—

1. इलाहाबाद
2. मद्रास
3. बम्बई
4. कलकत्ता
5. लाहौर

उपरोक्त में से कौनसा/से कथन सत्य है?

(A) केवल 1, 3 और 5 (B) 2, 4 और 5
(C) केवल 2, 3 और 4 (D) उपरोक्त सभी

उत्तर—[C]

व्याख्या—भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत् तीन उच्च न्यायालयों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई का गठन किया गया था।

2. संविधान के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. मूल संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है।
2. वर्तमान में प्रत्येक राज्य के पास एक उच्च न्यायालय है।

उपरोक्त में से कौनसा/से कथन सत्य है?

(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) न तो 1 और न ही 2

उत्तर—[A]

व्याख्या—संविधान के अनुच्छेद 214 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। वर्तमान में कुल 25 राज्यों के पास ही उच्च न्यायालय है।

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय हो सकता है।
2. वर्तमान में प्रत्येक संघ शासित प्रदेशों में अलग-अलग उच्च न्यायालय का गठन किया गया है।
3. पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ तीनों एक ही उच्च न्यायालय साझा करते हैं।

उपरोक्त में से कौनसा कथन असत्य है?

(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 1 और 3 (D) उपरोक्त सभी

उत्तर—[B]

व्याख्या—7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 में संसद को अधिकार दिया गया कि वह दो या दो से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। वर्तमान में केवल दिल्ली (संघ शासित प्रदेशों में से) में ही स्वयं का उच्च न्यायालय है। पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ तीनों का एक ही साझा उच्च न्यायालय है।

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 21 अन्य न्यायाधीश होते हैं।
2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्धारित की जाती है।

उपरोक्त में से कौनसा/से कथन असत्य है?

(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) न तो 1 और न ही 2

उत्तर—[C]

व्याख्या—संविधान के अनुच्छेद 216 में स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझें।

5. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-216 के शीर्षक के संदर्भ में कौनसा सही है?

(A) प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन।
(B) उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना।
(C) उच्च न्यायालयों का गठन।
(D) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति।

उत्तर—[C]

व्याख्या—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों के गठन की व्यवस्था की गई है जिनकी संख्या राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करेगी।

6. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?

(A) राज्य के राज्यपाल द्वारा (B) राज्य के विधानमण्डल द्वारा
(C) भारत के राष्ट्रपति द्वारा (D) केन्द्र सरकार द्वारा

उत्तर—[C]

व्याख्या—संविधान के अनुच्छेद-217 में प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी।

7. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति का स्वविवेक है।
2. न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है।
3. न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होता है।

उपरोक्त में से कौनसा/से कथन सत्य हैं?

(A) केवल 1 और 2 (B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3 (D) उपरोक्त सभी

उत्तर—[D]

व्याख्या—संविधान के अनुच्छेद-217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति व पद से हटाने का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति का स्वविवेकाधिकार है (अनु. 216)। न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होता है। यह अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी राष्ट्रपति को लिखित हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र दे सकते हैं।

1. सन् 1772 में बंगाल में सर्वप्रथम किसके द्वारा कलेक्टर का पद सृजित किया गया?

(A) वारेन हेस्टिंग्स (B) लॉर्ड कार्नवालिस
(C) जॉन शोर (D) लॉर्ड वेलेजली

उत्तर—[A]

व्याख्या—वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में 1772 में सर्वप्रथम कलक्टर के पद का सृजन किया, जिसे सन् 1773 में समाप्त कर दिया गया। 1781 में पुनः यह पद सृजित हुआ तथा सन् 1786 से जिले को राजस्व एकत्रण की महत्त्वपूर्ण इकाई स्वीकार करते हुए कलक्टर पद को अनेक अधिकारों से युक्त किया गया। **रात्फ शैल्डन** को ब्रिटिश शासन का प्रथम जिला कलक्टर माना जाता है।

2. निम्नलिखित में से कौनसा कार्य जिला दण्ड नायक के रूप में जिलाधिकारी नहीं करता है?

(A) विदेशियों के पारपत्र (पासपोर्ट) की जाँच करना।
(B) जाति, निवास प्रमाण-पत्र आदि जारी करना।
(C) शराब, पेट्रोल, औषधि तथा अन्य मादक पदार्थों पर आबकारी शुल्क पर नियंत्रण करना।
(D) तस्करी, नशीली दवा व्यापार संबंधी गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।

उत्तर—[C]

व्याख्या—शराब, पेट्रोल, औषधि तथा अन्य मादक पदार्थों पर आबकारी शुल्क पर नियंत्रण करना संबंधी कार्य जिलाधिकारी, जिला कलक्टर (राजस्व अधिकारी) के रूप में करता है न कि जिला दण्डनायक (जिला मजिस्ट्रेट) के रूप में।

3. जिले में जनगणना करवाना जिलाधिकारी द्वारा किये जाने वाले किन कार्यों की श्रेणी में आता है?

(A) राजस्व अधिकारी के रूप में किए जाने वाले कार्य।
(B) प्रशासनिक अधिकारी के रूप में किए जाने वाले कार्य।
(C) जिला दण्डनायक के रूप में किए जाने वाले कार्य।
(D) विकास अधिकारी के रूप में किए जाने वाले कार्य।

उत्तर—[B]

व्याख्या—जिला अधिकारी, जिला स्तर पर सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते, सभी विभागों का नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण करता है। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में प्रमुख कार्य –

- प्रशासनिक गतिविधियों हेतु वित्त व्यवस्था करना
- चुनावों में समस्त चुनावी व्यवस्थाएँ करवाना
- सैन्य अधिकारियों से सम्पर्क बनाए रखना
- विभिन्न प्रकार के आंकड़े, सांख्यिकी तथा तथ्यों को एकत्र करवाना

4. निम्नलिखित में से कौन-कौनसे कार्य जिलाधिकारी द्वारा जिला कलक्टर (राजस्व अधिकारी) के रूप में किए जाते हैं?

(1) भूमि अधिग्रहण की कार्यवाहियाँ करना
(2) जिला राजकोष पर नियंत्रण रखना
(3) कृषि ऋण वितरण की व्यवस्था करवाना
(4) सरकारी आवासों का आवंटन करना

कूटः-

(A) 1 और 2 (B) 2, 3 और 4
(C) 1, 2 और 4 (D) 1, 2 और 3

उत्तर—[D]

व्याख्या—**'कलक्टर'** का अर्थ **'एकत्र करने वाला'** होता है। ब्रिटिश काल में जिलाधिकारी का मुख्य कार्य **'राजस्व संग्रहण'** होता था, इसलिए उसे कलक्टर कहा जाता था। वर्तमान में भी जिलाधिकारी द्वारा किए जाने वाले कार्यों में **'राजस्व संग्रहण'** प्रमुख कार्य है।

- 'सरकारी आवासों का आवंटन करना' एक प्रशासनिक कार्य है, न कि राजस्व संग्रहण संबंधी कार्य।

राजस्व अधिकारी के अन्य महत्वपूर्ण कार्य

- कृषि आयकर, सिंचाई शुल्क, नहरी शुल्क, आयकर, बिक्री कर तथा अन्य आवश्यक करों को उगाहने में प्रशासनिक निर्देश प्रदान करना।

5. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है?

(A) जिला प्रमुख (B) जिला कलक्टर
(C) जिला विधायक (D) मुख्यमंत्री

उत्तर—[B]

व्याख्या—जिला स्तर पर जिला कलक्टर, आपदा निवारक अधिकारी के रूप में कार्य करता है। बाढ़, भूकम्प, सूखा, अकाल, तूफान, ओलावृष्टि, महामारी, युद्ध आदि परिस्थितियों में जिले में जिला कलेक्टर की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

6. अजमेर में राजस्व मण्डल की स्थापना कब की गई?

(A) 1949 (B) 1950
(C) 1955 (D) 1960

उत्तर—[A]

व्याख्या—राजस्व मण्डल, राजस्व प्रशासन में सर्वोच्च अभिकरण है, जो प्रशासनिक, न्यायिक, विधायी तथा नियंत्रण सहित संदर्भ का भी कार्य करता है।

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

(1) जिला दण्डनायक (मजिस्ट्रेट) राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (1980, रासुका) के तहत आदतन अपराधियों को नियंत्रित करता है।

(2) राजस्थान अभ्यस्त अपराधी अधिनियम, 1953 के अंतर्गत 'दस नम्बरी' व्यक्तियों पर निगरानी व नियंत्रण का कार्य जिला मजिस्ट्रेट का होता है।

कूटः-

(A) कथन (1) सही, (2) गलत है।
(B) कथन (1) गलत (2) सही है।
(C) दोनों कथन सही हैं।
(D) दोनों कथन गलत हैं।

उत्तर—[C]

व्याख्या—जिला मजिस्ट्रेट जिले में शांति, सुरक्षा, एकता, सद्भाव तथा व्यवस्था बनाए रखने हेतु उत्तरदायी है। इसके अंतर्गत जिला

1. निम्नलिखित में से कौनसी सिफारिश बलवंतराय मेहता समिति द्वारा नहीं दी गई?

1. पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों द्वारा होना चाहिए।
2. जिला परिषद का अध्यक्ष, जिलाधिकारी होना चाहिए।
3. पंचायती राज चुनावों में सभी स्तर पर राजनीतिक दलों की भागीदारी हो।

कूटः—

(A) केवल (2) (B) केवल (1)
(C) केवल (3) (D) 2 व 3 दोनों

उत्तर—[C]

व्याख्या— ''पंचायती राज चुनावों में सभी स्तर पर राजनीतिक दलों की भागीदारी हो'' यह सिफारिश ''अशोक मेहता समिति'' द्वारा की गयी थी।

बलवंतराय मेहता समिति– जनवरी 1957 में गठित इस समिति ने 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' की योजना की सिफारिश की। मेहता समिति की कुछ विशिष्ट सिफारिशें इस प्रकार हैं–

(1) त्रि-स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना—ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद्।
(2) ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होनी चाहिए।
(3) पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद् को सलाहकारी, पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए।
(4) इन निकायों द्वारा दायित्वों के निर्वाह हेतु उचित वित्तीय साधन सुलभ होने चाहिए।

2. निम्नलिखित में से कितने युग्म सुमेलित हैं?

(1) 1870-लॉर्ड मेयो द्वारा पंचायतों को कार्यात्मक व वित्तीय स्वायत्तता।
(2) 1909-विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन का प्रतिवेदन।
(3) 1952-सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ।
(4) 1985-जी.वी.के. राव समिति का गठन।

कूटः—

(A) केवल एक युग्म (B) केवल दो युग्म
(C) केवल तीन युग्म (D) सभी चारों युग्म

उत्तर—[D]

व्याख्या—उपर्युक्त दिए गए चारों युग्म सुमेलित हैं। इनके अतिरिक्त पंचायती राज के विकास के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण समितियाँ –

- 1961—पंचायती राज प्रशासन पर अध्ययन दल-बी. ईश्वरन्
- 1963—पंचायती राज वित्त पर अध्ययन दल-के. संथानम
- 1966—पंचायती राज निकायों के अंकेक्षण एवं लेखा पर गठित अध्ययन दल-के. संथानम

3. 1959 में सर्वप्रथम कौन-कौन से दो राज्यों में पंचायती राज की स्थापना हुई?

(A) राजस्थान व आंध्रप्रदेश (B) राजस्थान व पश्चिमी बंगाल
(C) राजस्थान व तमिलनाडु (D) राजस्थान व गुजरात

उत्तर—[A]

व्याख्या— राजस्थान देश का प्रथम राज्य था, जहाँ पंचायती राज की स्थापना हुई। 2 अक्टूबर, 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरु द्वारा नागौर में इसका उद्घाटन किया गया। 1959 में ही आंध्रप्रदेश में भी पंचायती राज संस्थाएँ स्थापित हुई। विभिन्न राज्यों ने भिन्न-भिन्न पंचायती राज प्रणालियों को अपनाया। उदाहरणतः राजस्थान में त्रि-स्तरीय पद्धति, तमिलनाडु में द्वि-स्तरीय पद्धति जबकि पश्चिमी बंगाल में चार स्तरीय पद्धति को अपनाया गया।

4. ''पंचायती राज संस्थाओं का नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण होना चाहिए'' यह सिफारिश किस समिति द्वारा प्रदान की गई?

(A) बलवंतराय मेहता समिति (B) अशोक मेहता समिति
(C) थुंगन समिति (D) जी.वी.के. राव समिति

उत्तर—[B]

व्याख्या— 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायतीराज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया गया। इस समिति की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं- द्विस्तरीय पद्वति—जिला परिषद् (जिला-स्तर पर) व मंडल पंचायत (ग्राम-समूह स्तर पर)

- जिला-परिषद्, कार्यकारी निकाय होना चाहिए।
- पंचायती-राज चुनावों में राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो।
- 'न्याय-पंचायतों' व 'विकास-पंचायतों' को अलग-अलग रखा जाना चाहिए।
- जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होने चाहिए।

5. निम्नलिखित समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए–

(1) जी.वी.के. राव समिति (2) अशोक मेहता समिति
(3) थुंगन समिति (4) एल.एम. सिंघवी समिति

कूटः—

(A) 1,2,3,4 (B) 2,1,4,3
(C) 2,1,3,4 (D) 2,3,1,4

उत्तर—[B]

व्याख्या—'पंचायती-राज' से संबंधित समितियों का सही कालक्रम निम्नानुसार है—

(1) अशोक मेहता समिति—दिसम्बर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने यह समिति गठित की थी। अगस्त 1978 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कुल 132 सिफारिशें थीं।

(2) जी.वी.के. राव समिति (1985)—तत्कालीन योजना आयोग द्वारा ''ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम'' की समीक्षा करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था।

(3) एल.एम. सिंघवी समिति (1986)—कांग्रेस सरकार द्वारा ''लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार'' विषय पर एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। इस समिति द्वारा पंचायती-राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने पर विशेष रूप से बल दिया गया था।

(4) थुंगन समिति (1988)—पंचायती राज संस्थाओं के राजनैतिक और प्रशासनिक ढाँचे की जांच करने के उद्देश्य से संसद की सलाहकारी समिति की एक उप-समिति के रूप में पी.के. थुंगन की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई था।

3. निम्नलिखित में से कौनसा/से कथन सत्य है/हैं ?

1. राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य दूसरे कार्यकाल के लिए पात्र नहीं होते हैं।
2. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी नौकरी/नियोजन के पात्र नहीं होते हैं।

कूट :-

(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

उत्तर—(C)

व्याख्या—किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य दूसरे कार्यकाल के पात्र नहीं होते हैं। आयोग के अध्यक्ष किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं तथा संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य या अध्यक्ष बनने के पात्र होते हैं। आयोग के सदस्य उसी आयोग के अथवा अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं तथा संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य या अध्यक्ष बनने के पात्र होते हैं। परन्तु वे किसी भी सरकारी (न तो केन्द्र न ही राज्य) नियोजन के पात्र नहीं होते हैं।

4. किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को जयपुर से अजमेर स्थानान्तरित किया गया था ?

(A) राम लुभाया समिति (B) शंकर देव राय समिति
(C) सत्यनारायण राव समिति (D) बलवन्तराय मेहता समिति

उत्तर—(C)

व्याख्या—राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 20 अगस्त, 1949 को जयपुर में की गई थी। 1956 में ''सत्यनारायण राव समिति'' की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को जयपुर से अजमेर स्थानान्तरित किया गया। इस समिति का गठन मार्च, 1949 में हुआ था, इसी समिति ने जयपुर को राजधानी, जोधपुर में न्याय विभाग और भरतपुर में कृषि विभाग स्थापित करने की सिफारिश की थी। ''शंकरदेव राय समिति'' का गठन धौलपुर व भरतपुर के लोगों का मत जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान व उत्तरप्रदेश में से किसमें विलय करना चाहते हैं। नए जिलों के गठन के संबंध में सुझाव देने के लिए ''राम लुभाया समिति'' का गठन किया गया था। बलवन्त राय मेहता समिति का संबंध पंचायती-राज व्यवस्था से है।

5. राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में कौनसा असुमेलित है?

(A) प्रथम अध्यक्ष :- डॉ. एस.के. घोष
(B) प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष :- श्री एस.सी. सिंजारिया
(C) स्वतंत्रता पूर्व लोक सेवा आयोग का गठन :- जोधुपर
(D) वर्तमान अध्यक्ष :- श्री संजय कुमार श्रोत्रिय

उत्तर—(B)

व्याख्या—प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष श्री एल.एल. जोशी थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष (जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश भी थे) डॉ. एस. के. घोष थे। अब तक आयोग के 6 कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं (श्री एल.एल. जोशी, श्री एस.सी. सिंजारिया, श्री एच.एन. मीना, डॉ. आर.डी. सैनी, डॉ. शिवसिंह राठौड़ और डॉ. जसवंत सिंह राठी)। राजस्थान के गठन व स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में 3 रियासतों के अपने लोक सेवा आयोग थे- जोधपुर (1939 में गठन), जयपुर (1940) व बीकानेर (1946)।

6. राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किन आधारों पर पद से हटाया जा सकता है:-

1. यदि उसे दिवालिया घोषित किया गया हो।
2. पदावधि के दौरान सवेतन नियोजन में लगा हो।
3. राष्ट्रपति के मत में मानसिक अथवा शारीरिक शैथिल्य के कारण पद के अयोग्य हो।

कूट :-

(A) केवल 1 और 3 (B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3 (D) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(D)

व्याख्या—अनु.-317 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को बर्खास्त एवं निलंबित किया जा सकता है। उपर्युक्त आधारों के अतिरिक्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को कदाचार के आधार पर भी हटाया जा सकता है, ऐसे मामलों को राष्ट्रपति न्यायालय में जाँच के लिए सौंपते हैं तथा जाँच में दोषी पाए जाने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है।

7. निम्नलिखित में से कौनसे कार्य राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा क्रियान्वित किये जाते है?

(A) राज्य सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन करवाना।
(B) पदोन्नति व स्थानान्तरण के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना।
(C) विभिन्न सेवाओं के लिए साक्षात्कार करवाना।
(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(D)

व्याख्या—राजस्थान लोक सेवा आयोग राज्य सरकार को किसी भी भर्ती की पद्धति, विभिन्न पदों पर नियुक्ति, स्थानान्तरण, पदोन्नति तथा किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित सलाह देता हैं विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन व अंतिम चयन के लिए साक्षात्कार करवाना भी आयोग का मुख्य कार्य है।

8. राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है ?

(A) राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष को
(B) राजस्थान के मुख्यमंत्री को
(C) राजस्थान के राज्यपाल को
(D) राष्ट्रपति को

उत्तर—(C)

व्याख्या—राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार राज्यपाल को सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 315(2) के तहत जब दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा का गठन किया जाता है, तब इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा पदमुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। परन्तु संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट संबंधित राज्यों के राज्यपालों को सौंपता है।

1. लोकनीति को लोकप्रशासन के पाठ्यक्रम में कब शामिल किया गया?

(A) वर्ष 1930 (B) वर्ष 1934
(C) वर्ष 1937 (D) वर्ष 1939

उत्तर—[C]

व्याख्या—वर्ष 1937 में हावर्ड विश्वविद्यालय के लोकप्रशासन के पाठ्यक्रम में लोकनीति को शामिल किया गया था। लोकनीति से तात्पर्य है-''विशिष्ट उद्देश्यों व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्य प्रक्रिया''
लोकनीति का उद्देश्य तथा संबंध सरकार द्वारा जनकल्याण के लिए बनाई गई नीति से है।

2. लोकनीति पर लिखी गई पहली मानक पुस्तक 'द पॉलिसी साइन्स' के लेखक कौन हैं?

(A) डेनियल लर्नर व लासवेल (B) चार्ल्स मेरियम
(C) पॉल जे. फ्रेडरिक (D) प्लोडन व टैरी

उत्तर—[A]

व्याख्या—

(1) लोकनीति पर प्रथम मानक पुस्तक **'द पॉलिसी साइन्स'** वर्ष 1951 में डेनियल लर्नर व लासवेल द्वारा लिखी गयी थी।

(2) **चार्ल्स मेरियम** ने 1922 में लोकनीति को परिभाषित करते हुए कहा कि ''सरकार की गतिविधियाँ ही लोकनीति है।''

(3) **पॉल. जे. फ्रेडरिक के अनुसार** – ''इस परिस्थिति में क्या करना है या क्या नहीं करना है, के संबंध में लिए गए निर्णय ही लोकनीतियाँ हैं।''

3. ''लोकनीति उस कार्यवाही का शाब्दिक, लिखित व विहित बुनियादी मार्गदर्शक है जिसे प्रबंधक अपनाता है और अनुगमन करता है।'' लोकनीति की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है?

(A) प्लोडन (B) जॉर्ज टैरी
(C) डिमॉक (D) थॉमस आर. डे

उत्तर—[B]

व्याख्या—लोकनीतिज्ञों के अनुसार ''लोकनीति'' की परिभाषाएँ-

(1) **'जॉर्ज टैरी' के अनुसार** ''लोकनीति उस कार्यवाही का शाब्दिक लिखित विदित बुनियादी मार्गदर्शक है, जिसे प्रबंधक अपनाता है तथा अनुगमन करता है।''

(2) **प्लोडन** – ''किसी देश की सरकार के प्रत्येक स्तर पर नीतियों का निर्माण किया जाता है, वे सब वास्तव में लोकनीतियाँ ही हैं।''

(3) **डिमॉक** – ''नीतियाँ सजगता से निर्धारित आचरण के वे नियम हैं, जो प्रशासकीय निर्णयों को मार्ग दिखाते हैं।''

(4) **थॉमस आर. डे** – ''सरकार जो कुछ भी करना चाहती है या नहीं करना चाहती, लोकनीति कहलाती है।''

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. लोकनीति सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है।
2. संवैधानिक प्रक्रिया पर आधारित होती है।
3. प्रशासनिक अधिकारियों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन लोकनीति के संबंध में सत्य है/हैं?

(A) केवल 1 (B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3 (D) उपरोक्त सभी

उत्तर—[D]

व्याख्या—लोकनीतियाँ किसी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित की जाती है। यह सरकार की गतिविधियों का एक सतत् एवं निश्चित क्रम है। नीतियाँ देश के सामान्य कानून अथवा संविधान पर आधारित होती है। यह समस्या समाधान की विधि है। यह **मार्गदर्शक** के रूप में भी कार्य करती है। यह नकारात्मक या सकारात्मक भी हो सकती है।

5. निम्नलिखित में से कौन-सा/से नीति निर्माण के अंग के रूप में शामिल होते हैं?

1. व्यवस्थापिका **2. दबाव समूह**
3. कार्यपालिका **4. नीति आयोग**

कूटः-

(A) केवल 1, 3 और 5 (B) केवल 1 और 3
(C) केवल 1, 2, 4 और 5 (D) उपरोक्त सभी

उत्तर—[D]

व्याख्या—सामान्यतः नीति निर्माण दो प्रकार के होते हैं—सरकारी व गैर-सरकारी। **सरकारी नीति**—निर्माण का कार्य कार्यपालिका करती है जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहते हुए नीति निर्माण करती है, जबकि गैर-सरकारी में दबाव समूह राजनीतिक दल व नागरिक भी नीति-निर्माण में भूमिका निभाते हैं। सरकार की नीतियाँ बनाने वाली सबसे बड़ी संस्थाओं में नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद् शामिल है। व्यवहार में नीति निर्माण की पूरी प्रक्रिया सरकारी और गैर-सरकारी तत्वों से आपस में प्रभावित होती है।

6. निम्न में से कौनसे घटक लोकनीति प्रक्रिया के प्रमुख घटकों में शामिल हैं?

(A) नीति-निर्धारण (B) नीति-क्रियान्वयन
(C) नीति-मूल्यांकन (D) उपरोक्त सभी

उत्तर—[D]

व्याख्या—लोक नीति प्रक्रिया के प्रमुख घटकः

(1) **नीति-निर्धारण (निमार्ण)**—नीति-निर्माण की प्राथमिक जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है।

(2) **नीति-क्रियान्वयन**—नीति-निर्माण के बाद उसे क्रियान्वयन के लिए व्यवहारिकता में परिणन किया जाता है।

(3) **नीति-मूल्यांकन**—नीति-निर्माण और कार्यान्वयन के बाद नीति की प्रभावशीलता को मापने के लिए उसका मूल्यांकन किया जाता है।

7. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से विकल्प नीति-आयोग के संबंध में असत्य है?

(A) नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया।
(B) नीति-आयोग एक संवैधानिक संस्था है।
(C) नीति-आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता हैं।
(D) इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था।

उत्तर—[B]

राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था
[Political & Administrative System of Rajasthan]

विगत वर्षों के प्रश्नोत्तर व्याख्या सहित
[Previous Years Q&A with Explanation]

राज्यपाल

1. गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था–

(A) 2 नवंबर, 1956 को (B) 25 अक्टूबर, 1956 को
(C) 1 नवंबर, 1956 को (D) 26 अक्टूबर, 1956 को

उत्तर–[*]

व्याख्या—राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 155 में किया गया है। राजस्थान राज्य का एकीकरण सात चरणों में सम्पन्न हुआ, जो 1 नवम्बर 1956 को वर्तमान स्वरूप में सामने आया। श्री गुरुमुख निहाल सिंह का राज्यपाल के रूप में कार्यकाल 1 नवम्बर 1956 से 15 अप्रैल 1962 रहा था।

(यह प्रश्न उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।)

2. किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुरः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया, अब–

(A) जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नही होगा।
(B) राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इंकार कर सकता है।
(C) राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा।
(D) यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा।

उत्तर–(A)

व्याख्या—संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्यपाल को विधानमण्डल द्वारा पारित साधारण विधेयकों को अनुमति देने के संबंध में शक्तियाँ दी गई हैं जिसके अंतर्गत वह स्वीकृति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, अनिश्चित समय के लिए अपने पास रख सकता है। यदि विधेयक संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, देश हित के विरुद्ध हो या उच्च न्यायालय की शक्तियाँ कम करता हो तो राज्यपाल, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं (अनुच्छेद 201)। न्यायालय किसी विधि के मूल अधिकारों के विरुद्ध होने, संविधान के मूल ढाँचे के खिलाफ होने पर ही उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है अन्यथा नहीं। अतः स्पष्ट है कि जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा।

3. राजस्थान राज्य में 30 जून, 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है?

(A) 5 बार (B) 3 बार
(C) 6 बार (D) 4 बार

उत्तर–(D)

व्याख्या—संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत प्रावधान किया गया है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के पश्चात् संघ राज्य की सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकता है जिसे सामान्य रूप से राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में 30 जून 2016 तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। वह इस प्रकार है –

1. 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक (44 दिन तक)
2. 29 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक (54 दिन तक)
3. 16 फरवरी 1980 से 6 जून 1980 तक (111 दिन तक)
4. 15 दिसम्बर 1992 से 4 दिसम्बर 1993 तक (354 दिन तक)

4. राजस्थान के राज्यपाल के रूप में श्री कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व, निम्नांकित में से कौन राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे?

(A) ओ.पी. कोहली (B) रामनरेश यादव
(C) राम नायक (D) मार्गरेट अल्वा

उत्तर–(C)

व्याख्या—राजस्थान के राज्यपाल श्री कल्याण सिंह का कार्यकाल 9 सितम्बर 2014 से 8 सितम्बर 2019 तक का रहा है। इनसे पूर्व राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल श्री रामनायक थे, जिनका कार्यकाल 8 अगस्त 2014 से 3 सितम्बर 2014 तक था जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे।

5. सही उत्तर चुनें–

राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं–

(A) सभी राज्य विश्वविद्यालयों के
(B) सभी राज्य विश्वविद्यालयों तथा राज्य में कार्यरत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के
(C) सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के
(D) सभी राज्य विश्वविद्यालयों, राज्य में स्थित में केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालयों के।

उत्तर–(A)

व्याख्या—संविधान के अनुच्छेद-154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों का प्रावधान किया गया है जिसके तहत राजस्थान का राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं।

DIVINE
CIVIL SERVICES ACADEMY

IAS • RAS

Rank Improvement Program *for* RAS MAINS

उन सभी के लिए जो रैंक सुधार करना चाहते है तथा उनके लिए भी जो प्रथम प्रयास में ही अच्छी रैंक प्राप्त करना चाहते है।

- अधीनस्थ सेवा अधिकारियों की मांग पर आधारित
- विख्यात विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन
- उत्तर लेखन पर विशेष बल
- गुणवत्ता सुधार हेतु विशेष प्रयास
- प्रत्येक विषय में अंक बढ़ाने हेतु विशेष रणनीति
- छोटा बैच साईज एवं व्यक्तिगत मार्गदर्शन

Offline/Online Batches

Download our app for online classes
Divine Civil Services Academy

Main Triveni Chauraha,
Gopalpura Bypass, Jaipur-302018

900-900-3843

राजस्थान प्रैक्टिस सीरीज़ की 4 पुस्तकें

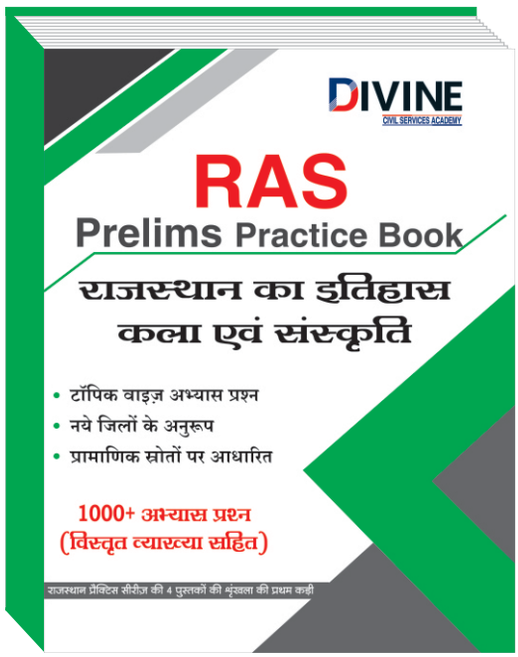

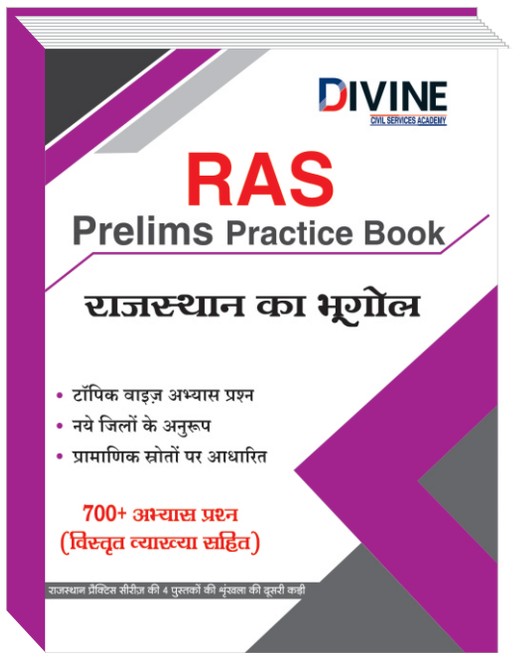

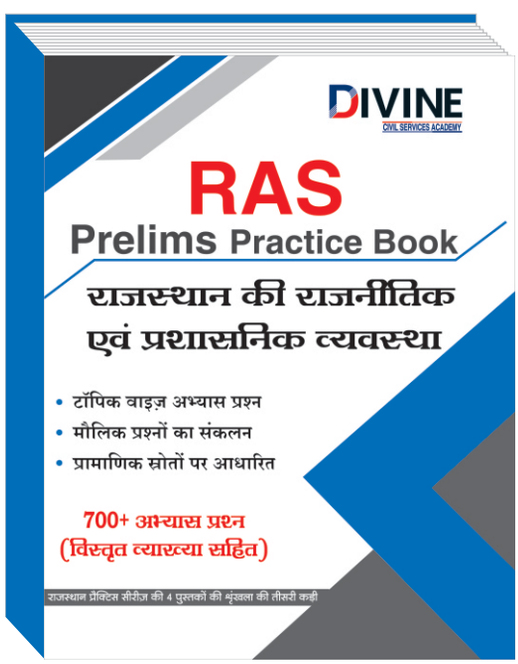

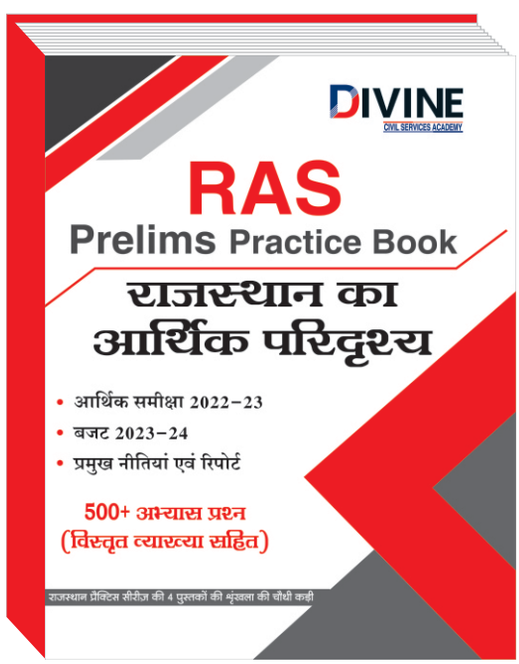

Divine Civil Services Academy
Main Triveni Chauraha, Gopalpura Bypass,
Jaipur-302018 ✆ **900-900-3843**
www.divinecivilacademy.com • email: divinecivilacademy@gmail.com

Code : 002

Fixed Price
₹ 100/-

For Trade Orders : College Book Centre, Jaipur ✆ **90010-72000**